

हरियाणा चुनाव कांटे की टक्कर

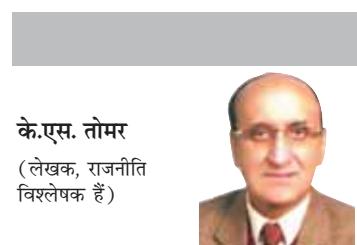
हरियाणा चुनाव में कांटे की टक्कर है। भाजपा-जजपा गठबंधन टूटने तथा कांग्रेस विद्रोहियों ने अनिश्चितता बढ़ाई है। 15 अक्टूबर, 2024 को चुनाव में हरियाणा का राजनीतिक परिदृश्य जबरदस्त टकराव तथा गठबंधनों में बदलाव से परिभाषित हो रहा है। यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी-भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिसने 2019 में दुष्प्रथं चौटाला की जननायक जनता पार्टी-जजपा के समर्थन से सरकार बनाई थी, पर अब वह अकेले चुनाव मेंदान में उतरी है। भाजपा-जजपा गठबंधन टूटने से भाजपा को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उसे चुनाव तक अल्पमत सरकार चलानी पड़ी है। अपने पूर्व सहयोगी जजपा के अलग होने के बाद सत्तारुद्ध भाजपा अपने विकास एजेंडे पर ध्यान केन्द्रित कर रही है। वह जनता को गिना रही है कि उसने ढांचागत विकास, शिक्षा तथा महिलाओं की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण काम किए हैं। लेकिन पार्टी को खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जहां कृषि सुधार जैसे मुद्दों पर भारी विरोध था। कांग्रेस स्वयं को भाजपा के मुख्य विकल्प के रूप में पेश कर रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में पार्टी को ग्रामीण क्षेत्रों में, खासकर जात मतदाताओं में व्यापक समर्थन मिलने की उम्मीद है और वह भाजपा सरकार के प्रति कथित असंतोष का लाभ उठाने का प्रयास कर रही है।



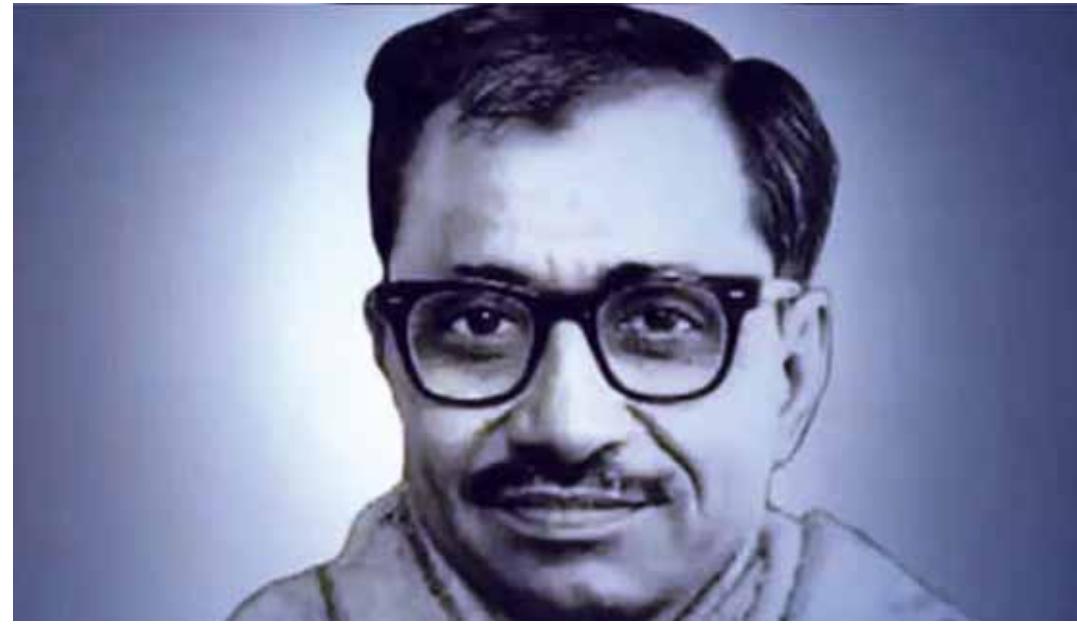
परिवार के दाना पर ज्ञान का प्रति
कर रही है। पिछले वर्षों में मजबूत पार्टी रही भारतीय राष्ट्रीय लोकदल-इनेलोद ने अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी-बसपा से हाथ मिलाया है। हरियाणा में कृषि क्षेत्र केन्द्रीय मुद्दा बना हुआ है। यह नए कृषि कानूनों पर किसानों के विरोध प्रदर्शनों से पैदा हुआ जिनको अब वापस ले लिया गया है। लेकिन सरकार के प्रति किसानों का गुस्सा अभी पूरी तरह ठंडा नहीं हुआ है। विपक्षी पार्टियां, खासकर कांग्रेस और जजपा इसका प्रयोग कर ग्रामीण मतदाताओं के लामबंद करने का प्रयास कर रही हैं। इसके साथ ही हरियाणा में भारत की सर्वाधिक बेरोजगारी दर है। भाजपा और कांग्रेस ने इसे हल करने का वादा किया है। भाजपा जहां अपनी औद्योगिक पहलें गिना रही है, वहीं कांग्रेस नई रोजगार नीतियों का प्रस्ताव कर रही है। इन सबके साथ ही राज्य में 'जातीय राजनीति' का दबदबा है जो सत्ता का निर्धारण करती है। परंपरागत जाट-गैर जाट विभाजन हरियाणा का राजनीतिक परिदृश्य परिभाषित करता है। भाजपा को परंपरागत रूप से गैर-जाट समुदायों का समर्थन मिलता रहा है, लेकिन उसके सामने इस जनाधार को मजबूत करने की चुनौती है। जजपा और कांग्रेस मुख्यतः जाट मतदाताओं पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। जातीय गणित हमेशा हरियाणा के राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण रही है। इसने मतदाताओं के व्यवहार और चुनाव परिणामों को प्रभावित किया है। हरियाणा की जनसंख्या में 25-30 प्रतिशत जाट सर्वाधिक प्रभावशाली राजनीतिक जाति समूह हैं। हुड़ा के नेतृत्व में कांग्रेस जाट तथा गैर-जाट के बीच खाई पाटने के लिए शहरी-ग्रामीण विकास योजनाओं पर ध्यान दे रही है, लेकिन उसे विप्रोहियों का सामना करना पड़ रहा है। 'जातीय गणित' का प्रबंधन करने वाले दल को ही राज्य में सत्ता मिलेगी।

एकात्म मानववाद : आदर्श एवं चुनौतियां

भाजपा पंडित दीनदयाल उपाध्यय की 108वीं जन्म जयंती मना रही है। उसके सामने 'एकात्म मानववाद' के आदर्शों तथा आधुनिक प्रशासन के बीच संगति बैठाने की चुनौतियां हैं।



भा रतीय जनता पार्टी - भजपा
आजकल दीनदयाल उपाध्यय
की 108वीं जन्म जयंती मना रही है।
उसके सामने 'एकात्म मानववाद' आदर्शों
तथा आधुनिक प्रशासन के बीच संगति
बैठाने की चुनौतियां हैं। भारतीय जनसंघ
के संस्थापक तथा 'एकात्म मानववाद' की
अवधारणा व आदर्श पेश करने वाले
स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्यय की 108वीं
जन्म जयंती मनाई जा रही है। ऐसे में
भाजपा के सामने चुनौती है कि वह इस
दूरदर्शी आदर्श के अनुकूल स्वयं को कहां
तक ढाल पाती है और इसे लागू करने में
कहां तक सफल होती है। दीनदयाल
उपाध्यय के 'एकात्म मानववाद' दर्शन में
विकास के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाया
गया है। इसमें मनुष्य की बेहतरी को ध्यान
में रखते हुए विकेन्द्रीकरण, स्वदेशी
संस्कृति, आत्मनिर्भरता तथा ऐतिक
प्रशासन पर जोर दिया गया है।



अवधारणा से टकराव है क्योंकि इसमें ग्रामीण व स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन, जमीनी स्तर पर रोजगारों के सुजन तथा विदेशी पूँजी पर निर्भरता घटाने को केन्द्र में रखा गया है। सरकार ने स्वदेशी संस्कृति और वैश्वीकरण के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया है। दीनदयाल

को बढ़ावा देने तथा शासन-प्रशासन से प्रभात्याकार समाप्त करने की कठिन चुनौती है। दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन में ऐतिक प्रशासन पर जोर दिया गया था जिसके प्रमुख तत्व निष्ठा, ईमानदारी तथा जनता की सेवा है। हालांकि, पिछले दशक में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली

विभिन्न विकास योजनाओं में सामाजिक व धर्मिक विभाजनों पर ध्यान नहीं दिया है, पर आलोचकों का आरोप है कि भाजपा विभाजनकारी नीतियां, खासकर धर्मिक आधार पर अपना रही है। हेंदुत्व-संचालित नीतियों तथा समावेशन व सामाजिक सामंजस्य के विचारों के

सुनिश्चित करना है। भाजपा ने 'सहयोगी संघवाद', जीएसटी तथा नीति आयोग के गठन जैसे कदम इस दिशा में उठाए हैं। प्रत्यक्ष लाभ हस्तातरण-डीबीटी तथा जनधन योजना ने नागरिकों का सशक्तीकरण सुनिश्चित करने के लिए बिचौलियों को हटाया है। इससे सभिसंडी तथा कल्याणकारी योजनायें सीधे लोगों तक पहुँची हैं।

कोविड-19 वैश्विक महामारी के समय शुरू की गई ‘आत्मनिर्भर भारत’ पहल के माध्यम से दीनदयाल उपाध्याय के आत्मनिर्भरता सिद्धान्त पर जोर दिया गया है। इसके माध्यम से स्थानीय विनिर्माण तथा घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ ही विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता घटाने के प्रयास किए गए हैं। इस प्रकार ‘मेक इन इंडिया’ पहल दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन के अनुरूप है। इसके माध्यम से घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ ही रोजगार सृजन को बढ़ावा मिला है। लेकिन वर्तमान समय में आधुनिक अर्थव्यवस्था का वैश्वीकृत चरित्र है। इसे देखते हुए पूर्णतः ऐसी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाना बहुत कठिन तथा चुनौतीपूर्ण है जिसका विश्व अर्थव्यवस्था तथा दूसरे देशों से कोई संबंध न हो।

भारतीय जनसंघ के संस्थापक तथा
महान् भारतीय दर्शनिक दीनदयाल
उपाध्याय के दर्शन को जमीन पर उतारने
का प्रयास जारी है। दीनदयाल उपाध्याय
के दर्शन को जमीन पर उतारने के प्रयास
में सत्तारूढ़ भाजपा को अनेक सफलतायें
मिली हैं, पर उसके समक्ष अनेक
चुनौतियाँ भी हैं। हालांकि, भाजपा को
राष्ट्रवाद, आत्मनिर्भरता तथा अंत्योदय को
बढ़ावा देने में अनेक अभूतपूर्व व
असाधारण उपलब्धियाँ प्राप्त हुई हैं, पर
उसे सच्चा आर्थिक विकेन्द्रीकरण लाने,
शासन-प्रशासन को पूर्णतः नैतिक बनाने
तथा सामाजिक सद्व्यवना को बढ़ावा देने
में काफी बाधाओं का सामना भी करना
पड़ रहा है। आधुनिक प्रशासन की
जटिलतायें, वैश्विक आर्थिक एकीकरण
तथा राजनीतिक रणनीतियाँ अक्सर भाजपा
को दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन से थोड़ा
विचलित करती हैं। लेकिन ‘एकात्म
मानववाद’ के आदर्श पार्टी के समक्ष
प्रकाश स्तंभ की तरह हैं जिससे वह
दर्शनिक आदर्श तथा समकालीन यथार्थ
के बीच बेहतर संतुलन स्थापित कर
बेहतर भारत बनाने का प्रयास कर रही है।

वैशिक व्यवस्था का पुनर्संतुलन

और अधिव्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं है और भारत शांति और स्थिरता की जल्द बहाली का समर्थन करने के लिए तैयार है। पिछले महीने न्यूयार्क में पश्चिम समिट के दौरान प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की थी। बैठक के बाद जारी एक प्रेस बयान में कहा गया, प्रधानमंत्री ने इजरायल-फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत की समय-परीक्षित सैद्धांतिक स्थिति को दोहराया और युद्ध विराम, बंधकों की रिहाई और बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आह्वान किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि केवल दो राष्ट्र समाधान ही क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता प्रदान कर सकता है।

A photograph showing a massive, billowing plume of dark smoke and fire rising from a residential area in Gaza City. The foreground is filled with the tops of numerous multi-story apartment buildings. The smoke column is thick and reaches high into the sky, with bright orange and yellow flames visible at the base where it meets the city buildings.

सरकार के नवनियुक्त प्रमुख मुहम्मद यूनुस को पश्चिमी नेताओं से बहुत जरूरी प्रशंसा मिल रही थी। यूनुस ने अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन, पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, अमेरिकी विदेश मंत्री, कनाडाई प्रधानमंत्री, यूरोपीय संघ के अध्यक्ष, विश्व बैंक और एडीबी के प्रमुखों से मुलाकात की। उन्होंने पाकिस्तान के

गर्मजोशी से मुलाकात की, जहां उन्होंने अपने द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने और क्षेत्रीय निकाय सार्क को पुनर्जीवित करने की इच्छा व्यक्त की। भारत के लिए, ये संबंध संभावित रूप से पाकिस्तान और चीन को बांगलादेश के साथ इस नए-नए दोस्ताना संबंध का उपयोग भारत के खिलाफ अपने विधवंसक एंडेंडों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।

जयशंकर ने न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में अपने भाषण में वैश्विक व्यवस्था को फिर से संतुलित करने पर बात की। उन्होंने कहा, वैश्विक व्यवस्था को फिर से संतुलित करना, जिसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के 51 संस्थापक सदस्यों से हुई थी, जो पिछले आठ दशकों में चौगुनी हो गई है, जहां आपके पास न केवल दुनिया में अधिक स्वतंत्र देश हैं, बल्कि वैश्विक व्यवस्था के व्यवस्थाएँ तभी आर्थिक जिनके अपने मजबूत हित हैं और जो उस हित को आगे बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। और इसलिए हम दुनिया के संदर्भ में जो कुछ भी देखते हैं, वह वास्तव में यह है कि दुनिया की अभिसरण की राजनीति वास्तव में कैसे होती है। और एक तीसरा शब्द जो मेरे दिमाग में आता है वह है बहुपक्षीयता। यह एक बहुत ही भद्दा शब्द है, लेकिन यह एक तरह से द्विपक्षीय संबंधों से परे एक ऐसी दुनिया का वर्णन करता है, जो व्यापकीय से क्षा है।

व्यक्तिगत सदस्यों का जावेक, राजनीतिक और यहां तक कि जनसांख्यिकीय भार भी स्थानांतरित हो गया है, एक ऐसे बिंदु पर स्थानांतरित हो गया है जहाँ हममें से कई लोग मानते हैं कि आज हम वास्तव में एक मोड़ पर हैं, मंत्री ने विकसित हो रही वैश्विक व्यवस्था को परिभाषित करने की कोशिश करते हुए यह बहुपक्षीय संसद में उत्तराधीनता अपने बहुपक्षीय संकेत है।

वह जहाँ देश इन अभिसरण और ओवरलैप के आधार पर संयोजन बनाते हैं, जिनके बारे में मैंने बात की है। और आपके पास वास्तव में देशों के समूहों की यह घटना है जो अक्सर एक सीमित एंजेंडे के लिए एक साथ आते हैं, कभी-कभी अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रापात शिखाते हैं।

एक हां सावधान में बहुत्सुवायता आर बहुलाद को सावधानी से लाया।
उन्होंने कहा, आज, हम सावत्र में एक वैशिक परिदृश्य को देख रहे हैं जो बहुत अधिक क्षेत्रीय है, जो, जैसा कि मैंने उन्हें देखा है, अधिक विस्तृत है।

हणे का लाभ

ज्ञानिगंगा भेदभाव

विंडबना है कि 78 साल की आजादी के बाद भी देश के कुछ राज्यों में ऐसी कारागार नियमावली है जहां जाति के आधार पर बैरक आबंटि की जाती है और काम दिया जाता है। इन कारागार नियमावलियों के अनुसार बंदी या हिरासती की जाति का उल्लेख जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय में देश के 11 राज्यों में जारी भेदभाव पर आधारित जेल नियमावली को निरस्त करने का आदेश दिया है। उसने तीन महीने में आवश्यक संशोधन का आदेश भी दिया है ताकि औपनिवेशिक काल के जातिगत भेदभाव वाले इन प्राविधानों को समाप्त किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय अत्यंत प्रशंसनीय है और इसे एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जाना चाहिए। इस प्रकरण से स्पष्ट है कि देश में अब भी अनेक ऐसे औपनिवेशिक कानून मौजूद हैं जिनको तुरन्त समाप्त किया जाना चाहिए। जातिगत भेदभाव के सभी रूपों तथा अपशृंगता की घटनाओं को पूरी तरह समाप्त करने के लिए सासन-प्रसासन और न्यायपालिका के साथ ही राजनीतिक दलों व सामाजिक संगठनों को पहल करनी चाहिए। जातिगत भेदभाव वाले ऐसे सभी प्राविधानों को समाप्त करना विकसित भारत तथा स्वस्थ समाज बनाना हेतु अनिवार्य है।

हिंज्जा
बाद
पैमाने
हैं। इ
साथ
उसवा
समय
लड़
करवे
पश्चि
इजरा
भी
विस्त
यूक्रे
पश्चि
विस्त
अर्थात्

यह का विस्तार

व के मारे जाने के जरायल पर बढ़े गिल हमले किए थे। पूरी मजबूती के जवाब दे रहा है। वह है कि वह इस घटनों से एक साथ वह सबको तबाह अमेरिका तथा इस युद्ध में वापर्थ है, लेकिन वे घटनों से युद्ध का तावहते हैं। रूस-पात्री रहने तथा में युद्ध का भारी नकारात्मक

रही है। अमेरिका में अगले महीने होने वाले चुनाव के दृष्टिकोण से भी डेमोक्रेट व रिपब्लिकन किसी प्रकार इजरायल व यहूदियों के समर्थन से पीछे हटना नहीं चाहते हैं। लेकिन युद्धविराम करवाना वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आसान नहीं है। एक साल पहले इजरायल पर हुआ हमला द्वितीय विश्वयुद्ध के समय यहूदियों के नरसंहार के बाव सबसे बड़ा हमला था। इजरायल की जनता तथा सरकार इस बारे अपने दुश्मनों का इस सीमा तक सफाया कर देना चाहते हैं कि वे उसके लिए निकट भविष्य में खतरा न बन सकें। वर्तमान

पैसे की गलामी

फिल्मी गीत-ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपैया बहुत मशहूर हुआ था। आज के समय में भी यह पूरी तरह प्रासांगिक है और शायद भविष्य में भी रहेगा। पैसा ही सब कुछ हो गया है और पैसे के लिए अनेक लोगों ने अपनी विश्वसनीयता व नैतिकता की लक्षण रेखा तोड़ दी है। एक अस्पताल की नर्स ने महज 5100 रुपए का नेंगे न मिलने पर एक नवजात शिशु की जान ले ली। इसी तरह दो युवकों ने डेढ़ लाख रुपए के आईफोन मंगवाकर डिलीवरी ब्वाय की हत्या कर दी। बहुत अफसोस की बात है कि रुपए पैसों के आगे इंसान की कीमत घास के तिनके से भी गई बीती हो गई है। कहा जाता है कि पहले हमारे देश में दया, करुणा व विश्वास की संस्कृति थी, लेकिन अब पैसे की गुलामी के चलते उसकी हत्या हो रही है। हालांकि, अब भी लोगों के खोए पैसे उनको तलाश कर लौटाने तथा पैसे के लालच में न पड़ कर अपरिचित लोगों की सेवा और उनकी रक्षा करने वाले लोग हैं, पर ऐसी सकारात्मक खबरें अक्सर खो जाती हैं। हमें ऐसे लोगों को सम्मान देना चाहिए।

-हेमा हरि उपाध्याय, खाचरोद

